

**न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली**

पीठासीन अधिकारी : डॉ० भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 23/2018 G.C.M.S. No. 2018/00163 दर्ज दिनांक : 11.06.2018

अपीलार्थिगण:

तेजाराम पुत्र गोमाजी, जाति चौधरी, निवासी चवरछा, तहसील आहोर  
जिला जालोर**बनाम**

प्रत्यर्थिगण:

1. अमीया देवी पत्नी छोगाजी, जाति चौधरी, निवासी गांगावा, तहसील आहोर जिला जालोर
2. उजी देवी पत्नी उमाजी, जाति चौधरी निवासी हरजी, तहसील आहोर, जिला जालोर
3. सदणो देवी पत्नी कसनाजी, जाति चौधरी, निवासी मणादर, तहसील शिवगंज जिला सिरोही
4. भूमिधारी तहसीलदार आहोर जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्धसहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 48/2016 अनवान सदणोबनाम तेजा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2017 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गतधारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार:-

1. श्री गुणेश सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स।
2. प्रत्यर्थिगण स्वयं उपस्थित।

**निर्णय**

दिनांक: 05.03.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरुद्ध सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 48/2016 अनवान सदणो बनाम तेजा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2017 के विरुद्ध आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है-

मौजा चवरछा तहसील आहोर के वर्तमान खसरा नम्बर 239, 240, 241, 249 कुल रकबा 12.27 हैक्टर में मोड़ाराम, हीराराम पिसरान वागा गवरी पत्नी वागा, सुन्दर, फैंन्सी पुत्रीया वागा, जेपा वल्द हेमा, रावता, सरूपा, भेरा पिसरान् वगता, तीजो पत्नी वगता, तेजा पुत्र गोमा 1/3 हिस्सा दर्ज था। इसके पुराने खसरा नम्बर 163, 164, 168, 169, 167 थे। इसके पुराने खसरा नम्बर 163, 164, 168, 169, 167 वगैरा थे इस भूमि से संबंधित म्युटेशन नम्बर 222 के विरुद्ध वर्तमान अपीलाण्ट ने सहायक कलेक्टर जालोर में म्युटेशन अपील संख्या 06/1982 तेजा बनाम सदणो वगैरा पेश की जिसमें वर्तमान तीनो रेषोडेन्ट पक्षकार थी उन तीनो ने लिखित में सहमति पेश की जिसमें वर्तमान तीनो रेषोडेन्ट पक्षकार थी उन तीनो ने लिखित में सहमति दी और स्वीकार



राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली

किया कि मेरी माता सोदी देवी ने दिनांक 05.07.79 को मुझे गोद लिया था पूरी जमीन तेजा के नाम दर्ज की जाती है तो हमे आपत्ति नहीं है। वादग्रस्त कृषि भूमि के करीबन 50 सहखातेदार दावा लाते समय तत्कालीन जमाबन्दी में दर्ज थे। जो सभी आवश्यक पक्षकार थे। उसमें केवल अपीलांट को पक्षकार बनाया अन्य को नहीं बनाया इस आधार पर मूल दावा ही खारिज योग्य था। जमाबंदी संवत 2040-2059 तहरीर करते समय वादी गण के पिता के स्थान पर प्रतिवादी तेजा का नाम दर्ज हो गया है जो बिना किसी आधार के दर्ज हुआ है। वादीगण रेस्पोंडेन्ट का मौके पर कभी कब्जा नहीं था, कब्जे के अभाव में खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की है। दावा दर्ज से निर्णय तक तेजाराम को सम्मन तामिल नहीं हुआ। विरोध में जवाबदावा आने के बावजूद तनकी नहीं बनाई। तनकी बनाकर तनकीवार निर्णय करना साक्ष्य लेखबद्ध नहीं की। वाद पत्र के साथ सलग्ग दस्तावेजो को प्रदर्श नहीं करवाया गया वादीगण स्वयं के बयान ही नहीं लिये गये। वादीगण ने दस्तावेजो व साक्ष्यो से दावे के कथनो को साबित नहीं किया। गोमा आज से 44 वर्ष पहले व सौदी करीब 40 साल पूर्व फौत हो चुके है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम संशोधित अधिनियम के प्रावधानों अनुसार 2005 से पहले मरे हुए माता पिता के मामलो में पुत्रीयो को कोई हक नहीं मिलता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।



म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है—

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से 03 द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2017 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील दिनांक 16.05.2018 को 60 दिवस के स्थान पर 306 दिवस के दीर्घ विलम्ब के साथ प्रस्तुत की गयी।
2. विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.07.2017 को होना बताया जा रहा है, अपीलांट अपने काम से दिनांक 04.04.2018 को अन्य पक्षकार के साथ आहोर गया तो पता चला कि तब अपीलांट को उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी प्राप्त हुयी है। अपीलांट अधिवक्ता की पुत्री की शादी दिनांक 29.04.2018 को थी, इस कारण अपील तैयार नहीं हो पाई। जिससे स्पष्ट है कि अपील प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है वह सद्भाविक हैं। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में डिले को कन्डोन किया जाना न्यायोचित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2017 को अपीलांट की उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई थीं। अधीनस्थ न्यायालय की दिनांक 14.07.2017 की आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर से इसकी पुष्टि होती है। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन व निर्णित प्रकरण की आरंभ से ही बखूबी जानकारी व संज्ञान था। अतः अपीलांट्स का यह कथन आधारहीन, काल्पनिक व अविश्वसनीय है कि उन्हें अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नहीं थीं। अतः अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की बखूबी जानकारी थी, साथ ही विलम्ब के प्रकरण में प्रार्थी को दिन-प्रतिदिन के विलम्ब के युक्तियुक्त व समुचित कारण दर्शित करने आवश्यक है लेकिन अपीलांट द्वारा ऐसा नहीं किया गया है।
4. अपीलांट्स प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों व उज्र के समर्थन में कोई दस्तावेज आदि पेश नहीं किए हैं। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा महज मौखिक कथन करते हुए विलम्ब के रूप में दर्शित कारण काल्पनिक रूप से अंकित किए हैं जो स्वीकार योग्य नहीं हैं। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री सक्षम न्यायालय द्वारा अपनी अधिकारिता के अंतर्गत उभयपक्षकारान की सुनवाई उपरांत पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को विधिविरुद्ध या आरंभतः शून्य प्रकरण भी नहीं माना जा सकता।
5. विलम्बकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :-

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5- condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.
2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.
3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is preferred after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforesaid provision cannotes that the dismissal is mandatory



राजस्व अपील  
प्राधी

subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or referred to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.

4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law- then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent



has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

6. हमने माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से 306 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित

राजस्व अपील प्राधिकारी  
माली

है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरुद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि 306 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

### आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
(डॉ० भास्कर बिश्नोई)

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

